



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष 1933 (श०)

(सं० पटना 822) पटना, वृहस्पतिवार, 29 दिसम्बर 2011

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

30 नवम्बर 2011

सं० 22/नि०सि०(जम०)-१२-१२/२००५/१४७७—श्री संजीवन चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, खरकई नहर प्रमण्डल, राजनगर सम्प्रति सेवा—निवृत के विरुद्ध उक्त प्रमण्डल में पदस्थापन अवधि में निविदा सूचना सं० ०१/२००३-०४ को बिना सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त किए हुए तोड़कर निविदा निकालने, इसके बिक्री हेतु अंचल कार्यालय एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय नहीं भेजे जाने, सरकारी आवास में रहते हुए निर्धारित मकान भाड़ा की कटौती नहीं करने एवं उनके मुख्यालय में दैनिक विश्राम आवास भत्ता के रूप में ३,८६७/- (तीन हजार आठ सौ सरसठ रुपये मात्र) एवं मकान भाड़ा के रूप में ६,६९६/- (छ: हजार छ: सौ छयानवे रुपये मात्र) अधिक राशि प्राप्त करने से संबंधित आरोपों के लिए श्री चौधरी के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली २००५ के नियम १९ के तहत विभागीय पत्रांक ९९८, दिनांक २४ अक्टूबर २००७ एवं ७४४ दिनांक १५ जुलाई २००६ द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त उक्त वर्णित आरोप प्रमाणित पाए गये। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं० ७५३, दिनांक ५ सितम्बर २००८ द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया।

- “निन्दन” वर्ष 2003-04
- पॉच वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
- 10,५६३/-रुपये (दस हजार पॉच सौ तिरसठ रुपये मात्र)

उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री चौधरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० सं० ८७११/०९ दायर किया गया जिसमें दिनांक ९ अगस्त २०११ को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा न्याय निर्णय पारित करते हुए उक्त वर्णित दण्डादेश दिनांक ५ सितम्बर २००८ के तीन दण्डों में से निम्नांकित दो दण्डों को निरस्त कर दिया गया।

- “निन्दन” वर्ष 2003-04
- पॉच वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तीसरा दण्ड १०,५६३/- रुपये की वसूली को बरकरार रखा गया।

उक्त वर्णित याचिका सी० डब्ल० जे० सी० सं० 8711/09 में दिनांक 9 अगस्त 2011 को पारित न्याय निर्णय की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा उक्त वर्णित याचिका में पारित न्याय निर्णय का अनुपालन करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में सी० डब्ल० जे० सी० सं० 8711/09 में दिनांक 9 अगस्त 2011 को पारित न्याय निर्णय का अनुपालन करते हुए श्री संजीवन चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, खरकई नहर प्रमण्डल राजनगर सम्प्रति सेवा—निवृत्त को विभागीय अधिसूचना सं० 753, दिनांक 5 सितम्बर 2008 द्वारा संसूचित तीन दण्डों में से निम्नांकित मात्र दो दण्डों को निरस्त किया जाता है।

1. “निन्दन” वर्ष 2003–04

2. पैंच वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

परन्तु तीसरा दण्ड 10,563/-रूपये (दस हजार पैंच सौ तिरसठ रूपये मात्र) की वसूली को यथावत रखा जाता है।

उक्त आदेश श्री चौधरी सेवा—निवृत्त अधीक्षण अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

भरत ज्ञा,

सरकार के उप—सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 822-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>